अध्यक्ष का संदेश ...

वार्षिक रिपोर्ट 2022–23

वर्ष 2023 भारत के लिए ऐतिहासिक वर्ष है जब वह अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है और 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा के 'अमृत काल' में प्रवेश कर रहा है. यह एक ऐसा महत्वपूर्ण मोड़ है जब भारत की विकासात्मक सोच और उसकी आर्थिक शक्ति ने उसे एक गौरवशाली स्थान दिलाया है और उसने जी-20 की अध्यक्षता संभाली है. भारत की अध्यक्षता में जी-20 का मुख्य विषय है 'वसुधैव कुटुंबकम' अथवा 'एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य'. साथ ही, उसकी प्राथमिकताएँ हैं - हरित समावेशी और आघात सह्य विकास.

बीते वर्ष विश्व में भू-राजनैतिक उथल-पुथल रही और आपूर्ति क्षेत्र को बड़े झटके लगे जिसके चलते विकास दर में कमी आई, मुद्रास्फीति बढ़ी और लगातार बनी रही, साथ ही अनिश्चितताएँ और गहराने लगीं जिसके कारण वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर संकट के बादल मँडराने लगे. ऐसे कठिन समय में भी, उल्लेखनीय दृढ़ता का परिचय देते हुए भारत ने संकट को अवसर में बदला और खुद को इस संकट से एक स्वर्ण युग में ले जाने का मार्ग खोज निकाला.

इस पृष्ठभूमि में, नाबार्ड ने एक विकास वित्त संस्था के रूप में सेवा के पाँचवें दशक में प्रवेश किया है जो भारत के प्रमुख विकास लक्ष्यों को पूरा कर रहा है और समग्र ग्रामीण समृद्धि का संवर्धन कर रहा है.

कृषि ऋण में अंतर-क्षेत्रीय असमानता को दूर करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, खासकर देश के मध्य क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में (जिनका फसल क्षेत्र में कुल हिस्सा 44% है और ऋण में हिस्सेदारी लगभग 24% है). ऋण तक पहुँच में व्याप्त असमानताओं, विशेष रूप से महिलाओं, लघु और सीमांत किसानों में, को दूर करने के लिए नाबार्ड उनके समूहीकरण और औपचारिक बैंकिंग में उनके समावेशन की अगुवाई कर रहा है. 'स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम'(एसएचजी-बीएलपी) नामक अपने अग्रणी कार्यक्रम के साथ-साथ संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) के गठन और बैंक लिंकेज के माध्यम से वे अंतिम सिरे पर रहने वालों को भी ऋण उपलब्ध करा रहा है. हमें गर्व है कि हमने 16.2 करोड़ ग्रामीण परिवारों की महिलाओं का सशक्तीकरण किया है. स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत वे बचत करती हैं, ऋण ले सकती हैं और उद्यम शुरू कर सकती हैं. नाबार्ड अब सक्रियता से, नई पहलों के माध्यम से, यह प्रयास कर रहा है कि स्वयं सहायता समूह अपनी पूरी संभावनाओं को साकार करें, उन्नत होकर कृषक उत्पादक संगठनों का गठन करें और सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करें. इससे संधारणीय आजीविका के विकल्प सृजित किए जा सकेंगे जिससे ग्रामीण जनता का आर्थिक-सामाजिक विकास होगा.

वर्षों से, नाबार्ड ने ग्रामीण भारत में औपचारिक ऋण, सूक्ष्म वित्त और सहकारिता की व्यवस्था को मेहनत और लगन से उन्नत किया और उसे आकार दिया, जिसमें हमें सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), साझेदार एजेंसियों और अन्य हितधारकों से पूरा सहयोग प्राप्त हुआ. ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं, विशेष रूप से सहकारी संस्थाओं के लिए प्रयासों को मजबूत करने और उन्हें प्रभावशाली बनाने के लिए किफ़ायती तरीके से डिजिटलीकरण को अपनाना जरूरी है ताकि किसानों, आपूर्तिकर्ताओं, खुदरा विक्रेताओं, उपभोक्ताओं, बैंकरों और अन्य हितधारकों के बीच सूचना विषमता को कम किया जा सके और किसानों की आय बढ़ाई जा सके. इस दिशा में, नाबार्ड, भारत सरकार के सहयोग से अगले पाँच वर्ष में 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के कम्प्यूटरीकरण के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को लागू कर रहा है जिसके माध्यम से सहकारी समितियाँ कोर बैंकिंग समाधानों को अपना सकेंगी, लेन-देन त्वरित होंगे, भुगतान सेवाओं तक निर्बाध पहुँच बनेगी और प्रभावी पर्यवेक्षण किया जा सकेगा. इसके अतिरिक्त, इस वर्ष नाबार्ड ने संगठन के भीतर उत्पन्न डेटा को संचित करने और ग्रामीण भारत की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयोजन से विस्तृत विश्लेषण-आधारित सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए अपना स्वयं का एंटरप्राइज़ डेटा वेयरहाउस सफलतापूर्वक निर्मित कर लिया है.

भंडारण की आधारभूत संरचनाओं की कमी के कारण फसल की कटाई के बाद होने वाली हानियाँ तथा टमाटर, प्याज और आलू जैसे शीघ्र नष्ट होने वाले कृषि उत्पादों की कीमतों में उतार-चढ़ाव किसानों और उपभोक्ताओं के लिए समान रूप से चिंता का कारण हैं. सहकारी क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा खाद्यान्न भंडार बनाने की भारत सरकार की योजना किसानों द्वारा मजबूरन बिक्री को रोकने, आयात पर निर्भरता को कम करने और ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसर पैदा करने में सहायक सिद्ध होगी. नाबार्ड में हमने इस भागीरथ प्रयास को सफल बनाने का बीड़ा उठाया है. इस कार्यक्रम के साथ 10,000 एफपीओ को बढ़ावा देने की केंद्रीय क्षेत्र योजना और ईएनडब्ल्यूआर (इलेक्ट्रॉनिक - परक्राम्य वेयरहाउस रसीद) के बीच संभावित तालमेल को देखते हुए यह कार्यक्रम किसानों की आय बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा.

नाबार्ड, अपने अधिदेश के अनुरूप, आधारभूत संरचनाओं और कृषि के वित्तपोषण के क्षेत्र में प्रभाव निवेश और नवोन्मेष में अग्रणी रहा है. बीते वर्षों में, ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं के वित्तपोषण हेतु राज्य सरकारों को मंजूर सहायता की संचयी राशि ₹5.0 लाख करोड़ तक पहुँच गई है, जिसमें कृषि, ग्रामीण संपर्क और सामाजिक क्षेत्र की 7.7 लाख से भी अधिक परियोजनाएँ शामिल हैं. हमारी प्रमुख आधारभूत संरचना निधि 'आरआईडीएफ' से 376 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ, 5.4 लाख किलोमीटर की ग्रामीण सड़कों और 13.3 लाख मीटर के ग्रामीण पुलों का निर्माण किया गया और 3,029.2 करोड़ व्यक्ति दिवसों के लिए गैर-आवर्ती रोजगार का सृजन हुआ.

देश में क्षेत्रीय सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को कम करने पर विशेष ध्यान देते हुए नाबार्ड इस क्षेत्र में पूंजी निर्माण का संवर्धन कर रहा है, जिसके लिए वह विभिन्न निधियों के माध्यम से सार्वजनिक और निजी निवेश की दिशा में कार्य कर रहा है. ये निधियाँ हैं- ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ), नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास सहायता (नीडा), फेडरेशनों के लिए ऋण सुविधा (सीएफएफ), प्रत्यक्ष पुनर्वित्त सहायता (डीआरए), डेयरी आधारभूत संरचना विकास निधि (डीआईडीएफ), मत्स्यपालन और जलचर पालन आधारभूत संरचना विकास निधि (एफआईडीएफ), भंडारागार आधारभूत संरचना विकास निधि (डब्ल्यूआईएफ), आदि. निधियों के उपयोग में और अधिक दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए, नाबार्ड ने वर्ष के दौरान 'नैबपरीक्षण' नामक डिजिटल एप्लिकेशन शुरू किया जिसके माध्यम से नाबार्ड द्वारा प्रदत्त पुनर्वित्त से सृजित आस्तियों का सक्रिय अनुप्रवर्तन और सत्यापन किया जा सकेगा.

जलवायु परिवर्तन, एक प्रमुख वैश्विक जोखिम है जो भारतीय कृषि के संधारणीय विकास के मार्ग में सबसे तगड़ी चुनौती के रूप में उभरकर समाने आया है. अत: कृषि को संधारणीय बनाने की दृष्टि से अनुकूलन और शमन परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण हो जाता है जिसके साधन हैं- प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन, फसल विविधीकरण, एकीकृत पोषक-तत्व प्रबंधन आदि. इस दिशा में हमने सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय संधारणीयता प्राप्त करने की दिशा में अनेक पहलें की हैं और वर्ष 2030 तक संयुक्त राष्ट्र के संधारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने में केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं और देश को सहयोग दे रहे हैं. नाबार्ड ने अनुदान सहायता के माध्यम से वाटरशेड और जनजातीय विकास कार्यक्रमों का संवर्धन किया है, जिससे मिट्टी और जल संरक्षण संभव हुआ और कृषि वानिकी के विकास में मदद मिली. साथ ही, तीन महत्वपूर्ण जलवायु निधियों के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई (एनआईई) होने के नाते नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन सह्य कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके तहत उसने ₹1,852.6 करोड़ की 40 परियोजनाओं का वित्तपोषण किया है.

जलवायु आघात सह्य कृषि के महत्व को समझते हुए, संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को 'अंतरराष्ट्रीय श्रीअन्न वर्ष' घोषित किया है. अनुकूल कृषि और सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थितियों के साथ, श्रीअन्न उत्पादन भारत के लिए एक अनूठा अवसर है जिसके जरिये देश खाद्य सुरक्षा से आगे पोषण सुरक्षा की ओर बढ़ सकता है. नाबार्ड ने श्रीअन्न की खेती करने वाले किसानों के साथ सहयोग के प्रयासों में तेजी लाई है. इस पहल के अंतर्गत कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का क्षमता निर्माण किया गया और अन्य हितधारकों के साथ सहयोग किया गया. श्रीअन्न के पोषण संबंधी लाभों और इसके लिए बाज़ार की संभाव्यताओं को देखते हुए, नाबार्ड ने श्रीअन्न के संबंध में जागरूकता लाने और उनके लिए प्रभावी योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए इस वार्षिक रिपोर्ट का मुख्य अध्याय श्रीअन्न पर ही रखा है.

अपनी स्थापना के बाद से ही नाबार्ड ने समावेशी और संधारणीय ग्रामीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया है जिसके तहत वह सरकार और अन्य हितधारकों की पहलों के लिए सहायता भी प्रदान करता है और उनके लिए पूरक उपाय भी करता है. हमने ग्रामीण इलाकों में ऋण व्यवस्था को मजबूत करने और जमीनी स्तर की संस्थाओं (स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, कृषक उत्पादक संगठन) को विकसित करने के लिए अभिनव मॉडल तैयार किए हैं, पुनर्वित्त और रियायती ऋण के माध्यम से सामाजिक क्षेत्रों हेतु सहायता प्रदान की है और आजीविका के संवर्धन के लिए संधारणीय मॉडल विकसित किए हैं.

वर्ष 2022-23 समाप्त हो गया है, आज नाबार्ड को अपनी सुदृढ़ता का एहसास तो है ही, साथ ही उसमें एक विचारशीलता भी मौजूद है जिसके परिणामस्वरूप उसने "प्रगति 1.0: कल से परे: नाबार्ड@2028" नामक अपना पहला रणनीतिक आयोजना दस्तावेज तैयार किया है. 'प्रगति' एक अच्छी तरह सुविचारित, संस्थागत प्रतिक्रिया है जो यह दर्शाती है कि हम कैसे अगले पाँच वर्षों में एक-साथ मिलकर आगे बढ़ने की योजना बना रहे हैं.

नाबार्ड भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, अपने बैंकिंग भागीदारों, ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं, सहकारिताओं, आधार स्तरीय नागरिक सामाजिक संगठनों तथा अन्य विकास सहयोगियों, और इन सबसे बढ़कर समस्त कृषक समुदायों और भारत की ग्रामीण जनता द्वारा प्रदान किए गए सहयोग के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है. मैं पूरे नाबार्ड की ओर से आशा और विश्वास दिलाता हूँ कि हम प्रभावी नीति निर्माण में रचनात्मक भूमिका निभाना जारी रखेंगे और अधिकाधिक ऊर्जा के साथ नए प्रयोग करते रहेंगे.

मुझे भरोसा है कि ग्रामीण भारत के समग्र आर्थिक विकास हेतु सहायता प्रदान करने; कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने; तथा किसानों और ग्रामीण आबादी के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की नाबार्ड की यह यात्रा आने वाले वर्षों में और गहरी एवं व्यापक होगी, तथा इसके और अधिक सार्थक परिणाम प्राप्त होंगे.

शाजी के. वी.
अध्यक्ष